मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक ली। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश भी दिए।

'रोडवेज ड्राइवर, कंडक्टर व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण सेमीनार आयोजित करें'

मुख्यमंत्री भजनलाल ने परिवहन, सड़क सुरक्षा विभाग व रोडवेज़ की समीक्षा बैठक ली

- मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि बसों में ऐसी सुविधायें उपलब्ध करायें कि कार वाले भी बस में यात्रा करने के लिए प्रेरित हों।
- उन्होंने कहा, ओवर लोड व ओवर स्पीड वाहन चालकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही व निगरानी होनी चाहिए।

जयपुर, 30 मई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन व्यवस्था को अधिक सुदृढ़, सुरक्षित एवं सुविधायुक्त बनाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करके कार्ययोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान रोडवेज की बसों में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, जिससे कार वाले भी बसों में यात्रा के लिए प्रेरित हों।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री निवास पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग और राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने रोडवेज चालक, परिचालक सहित सभी कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण सेमिनार आयोजित कराने के निर्देश दिए। उन्होंने रोडवेज बस स्टैंड और विश्राम स्थलों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने और उन्हें एक ही रंग में विकसित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पथ परिवहन निगम भविष्य को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार करे। सुरक्षित सफर के साथ बसों में भोजन और सरस उत्पाद उपलब्ध कराने का नवाचार किया जाए। उन्होंने प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के लिए समर्पित रूट बनाकर बसों का समयबद्ध संचालन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों में कैमरे और जीपीएस स्थापित करें और लोक परिवहन बसों का भी कलर निर्धारण करें।

शर्मा ने पद दुरूपयोग करने वाले कार्मिकों, ओवरलोड और ओवरस्पीड वाहन चालकों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई और निगरानी के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवीन परमिट जारी करने से पहले रूट निर्धारण करें, जिनमें अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, राजकीय कार्यालयों का विशेष ध्यान रखा जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क सुरक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को परिवहन नियमों की पालना करनी चाहिए, तभी सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने में इलेक्ट्रिक वाहनों की महत्वपूर्ण भूमिका है।इस दौरान उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित सम्बंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

गाज़ा में अस्थायी युद्ध विराम पर इज़रायल ने सहमति दी

वाशिंगटन, 30 मई। अमेरिका के वाइट हाउस ने कहा कि इजरायल ने गाजा में 60 दिन के युद्ध विराम प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

वाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने एक प्रेस ब्रीफिंग में, पुष्टि की कि पश्चिम एशिया में अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने हमास को युद्ध विराम प्रस्ताव सौंपा है, जिसका इजरायल ने समर्थन किया है।

- अमेरिका ने बताया कि यह युद्ध विराम 60 दिन का होगा।

लेविट ने कहा, हमास को भेजे जाने से पहले इजरायल ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए थे। मैं यह भी पुष्टि कर सकता हूं कि वे चर्चाएं जारी हैं, और हमें उम्मीद है कि गाजा में युद्ध विराम होगा ताकि हम सभी बंधकों को घर वापस ला सकें। सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, एक इजरायली अधिकारी और मामले से परिचित एक अमेरिकी सूत्र ने पुष्टि की कि प्रस्तावित समझौते में न केवल 60-दिवसीय युद्ध विराम शामिल है, बल्कि 10 जीवित बंधकों और 18 मृत बंधकों के अवशेषों को रिहा करने की योजना भी शामिल है।

हिन्दुस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर्नाटक के मंत्री ने यह भी अफसोस जताया कि इतने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, 2022-23 में रक्षा कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु को आवंटित किया गया, कर्नाटक को नहीं। योगदान और योग्यता के आधार पर इसका हकदार कर्नाटक है। मंत्रियों ने यह भी कहा कि वे इस मुद्दे पर केन्द्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या ''पूर्ण'' हुई

तीन न्यायाधीशों के शपथ ग्रहण के साथ ही सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 हो गई है

- सी.जे.आई. बी.आर. गवई ने सुप्रीम कोर्ट के ऑडिटोरियम में तीन नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई।

नयी दिल्ली, 30 मई। उच्चतम न्यायालय में नवनियुक्त तीन न्यायाधीशों ने शुक्रवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने शीर्ष अदालत परिसर के एक सभागार में आयोजित समारोह में न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया, न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति ए एस चंदुरकर को शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद की शपथ दिलाई। उनके शपथ ग्रहण करने के साथ ही उच्चतम न्यायालय के लिए कुल निर्धारित 34 न्यायाधीशों की संख्या पूरी हो गई।

शपथ ग्रहण समारोह में शीर्ष अदालत के अन्य न्यायाधीशों के अलावा अनेक वरिष्ठ अधिवक्ता और गणमान्य लोग मौजूद थे। इस महीने उच्चतम न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति ए एस ओका के सेवानिवृत्त होने के बाद शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों के तीन पद खाली हो गए थे।

न्यायमूर्ति गवई की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की कोलीजियम ने 26 मई 2025 को विभिन्न उच्च न्यायालयों के तीन मुख्य न्यायाधीशों को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के पद पर पदोन्नत करने की सिफारिश की थी।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की मुहर के बाद केंद्र सरकार ने गुरुवार को न्यायमूर्ति अंजारिया, न्यायमूर्ति बिश्नोई और न्यायमूर्ति चंदुरकर को शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की अधिसूचना जारी की थी।

शीर्ष अदालत के न्यायाधीश पद की शपथ लेने से पहले न्यायमूर्ति अंजारिया कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, जबकि न्यायमूर्ति बिश्नोई गुवाहाटी उच्च न्यायालय के और न्यायमूर्ति चंदुरकर बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे। अहमदाबाद के मांडवी-कच्छ में 23 मार्च, 1965 को वकीलों के परिवार में जन्मे न्यायमूर्ति अंजारिया के पिता भी न्यायपालिका में थे। अंजारिया अगस्त 1988 से वरिष्ठ अधिवक्ता एस एन शेलत के चैंबर में शामिल होकर गुजरात उच्च न्यायालय में वकालत शुरू की और वे संवैधानिक मुद्दे और सभी श्रेणियों के सिविल मामलों, श्रम और सेवा से जुडे मामलों में वकालत कर चुके हैं। न्यायमूर्ति अंजारिया ने 25 फरवरी, 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

न्यायमूर्ति बिश्नोई का जन्म 26 मार्च, 1964 को जोधपुर में हुआ था। उन्होंने आठ जुलाई, 1989 को अधिवक्ता के रूप में अपना पंजीकरण करवाया। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और जोधपुर में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सेवा, चुनाव मामलों आदि जैसे कई क्षेत्रों में वकालत की। उन्होंने वर्ष 2000-2004 के दौरान केंद्र सरकार के स्थायी वकील के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं।

न्यायमूर्ति बिश्नोई को आठ जनवरी, 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने सात जनवरी, 2015 को राजस्थान उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्होंने पांच फरवरी, 2024 को गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य शुरू किया।

न्यायमूर्ति चंदुरकर का जन्म सात अप्रैल, 1965 को हुआ था। मुंबई के वरिष्ठ अधिवक्ता बी एन नाइक के मार्गदर्शन में उन्होंने वकालत शुरू की, जिन्हें बाद में न्यायपालिका में पदोन्नत किया गया। न्यायमूर्ति चंदुरकर 1992 में नागपुर चले गए और विभिन्न न्यायालयों में वकालत की और अलग-अलग प्रकृति के मामलों को सफलतापूर्वक संभाला। उन्हें 21 जून, 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। बाद में वे वहां चीफ जस्टिस बने।

पहलगाम ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ऐशन्या और शुभम के पिता की आंखों से आंसू निकल आए, जिन्हें देखकर प्रधानमंत्री ने उन्हें ढ ांढ स बंधाया।

मोदी ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ चलाया जा रहा ऑपरेशन 'सिंदूर' रुका नहीं है, बल्कि यह आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने परिजनों को आश्वस्त किया कि सरकार उनके साथ है और आगे भी मुलाकात होती रहेगी।

शुभम द्विवेदी के परिजनों को नरवल एसडीएम की देखरेख में कार से चकेरी एयरपोर्ट लाया गया था।

''हम पहलगाम की घटना ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सरहद पर अतिरिक्त सेनाएं तैनात कर दी थीं। संघर्ष के बाद, सार्वजनिक रूप से बोलने वाले पाकिस्तानी सेना के वरिष्ठतम अधिकारी जनरल मिर्ज़ा ने कहा, ''हम करीब-करीब 22 अप्रैल की स्थिति पर वापस आ गये हैं। - - हम उस स्थिति पर पहुंचने वाले हैं, वैसे हमें उस स्थिति पर अब तक पहुंच जाना चाहिए था।''

जनरल मिर्ज़ा, जो इस समय ''शाँगरी-ला डायलॉग'' फोरम में शामिल होने के सिलसिले में सिंगापुर में हैं, ने कहा कि इस संघर्ष में, न्यूक्लियर हथियारों की तरफ कदम भले ही नहीं बढ़े हों, लेकिन स्थिति बहुत खतरनाक थी।

उन्होंने कहा, ''इस बार कुछ नहीं हुआ। लेकिन किसी भी समय किसी भी प्रकार के गलत रणनैतिक अनुमान की संभावना खारिज नहीं की जा सकती, क्योंकि जब संकटपूर्ण स्थिति होती है, उस समय प्रतिक्रियाएं भिन्न प्रकार की होती हैं।''

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में तनाव बढ़ने का खतरा बढ़ गया है, क्योंकि इस बार की लड़ाई कश्मीर, जो हिमालय की गोद में स्थित प्राकृतिक सौंदर्य से संपन्न क्षेत्र है, की जमीन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहा कि दोनों देशों का कश्मीर के कुछ-कुछ हिस्से पर शासन है, लेकिन दोनों ही देश पूरे कश्मीर पर अपना दावा प्रस्तुत करते हैं। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में स्थित सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन किसी ने भी किसी गंभीर नुकसान की बात स्वीकार नहीं की है।

भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस माह पाकिस्तान को चेतावनी दी थी कि अगर भारत पर फिर से हमले किये गये तो सीमा पार के ''आतंकी ठिकानों'' को निशाना बनाया जायेगा।

दोनों देशों के बीच तीन बड़े युद्ध हुए हैं, जिनमें दो कश्मीर को लेकर ही हुए हैं, वैसे तो अनेक सशस्त्र झड़पें हुई हैं, क्योंकि दोनों ही देशों का जन्म 1947 में ब्रिटिश उपनिवेश भारत से ही हुआ है।

भारत कश्मीर में विद्रोह का आरोप पाकिस्तान पर लगाता है, जिसकी शुरूआत 1989 में हुई और उसमें अब तक दसियों हजार लोग मारे गये हैं। पाकिस्तान का कहना है कि वह तो आत्म-निर्णय की दिशा में बढ़ रहे कश्मीरियों को केवल नैतिक, राजनैतिक एवं कूटनीतिक समर्थन एवं सहयोग देता है।

मिर्ज़ा ने कहा, ''भविष्य के लिहाज से, इन दोनों ही पड़ोसी न्यूक्लियर ताकतों के बीच और ज्यादा खतरनाक हथियारों के इस्तेमाल की संभावना बढ़ गई है, और फिर यह संघर्ष केवल विवादित भूभाग तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह पूरे भारत और पूरे पाकिस्तान को अपनी चपेट में ले लेगा। यह बहुत ही खतरनाक संकेत है।''

'नीट पीजी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निर्देश दिया। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि परीक्षा दो पालियों में आयोजित न करें, क्योंकि इससे उम्मीदवारों को समान अवसर नहीं मिलेंगे। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि दो पालियों में परीक्षा होने से मनमानी होगी और सामान्यीकरण प्रक्रिया को नियमित तरीके से लागू नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं दो पालियों की परीक्षा में प्रश्नपत्र कभी भी एक ही कठिनाई स्तर के नहीं हो सकते। शीर्ष अदालत ने कहा,हम यह स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि इस देश में तकनीकी प्रगति को देखते हुए देशभर में परीक्षा आयोजित करने वाली इस संस्था को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पाए।

अदालत ने कहा कि यदि अधिकारियों को लगता है कि वे परीक्षा केंद्रों की पहचान करने और 15 जून को परीक्षा आयोजित करने में सक्षम नहीं हैं तो वे परीक्षा की तिथि आगे बढ़ ाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

गृह मंत्री शाह ने पुंछ का दौरा किया

शाह पुंछ में पाक गोलीबारी से प्रभावित लोगों से मिले और नियुक्ति पत्र दिए

- शाह ने कहा, सरकार प्रभावित परिवारों के लिए जल्दी ही एक अलग पैकेज की घोषणा करेगी।
- ज्ञातव्य है कि पाक गोलीबारी में पुंछ सर्वाधिक प्रभावित हुआ, यहां 14 नागरिक मारे गए।

जम्मू, 30 मई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को फिर से परिभाषित किया है कि आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते तथा पानी और और खून भी एक साथ नहीं बह सकते।

पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे शाह ने कहा कि मोदी के नेतृत्व में भारत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नागरिकों पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसका अधिक प्रभावी और सटीक तरीके से जवाब दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मोदी के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद सीमावर्ती इलाकों में बंकर बनाने का फैसला लिया गया था। अब तक 9,500 से अधिक बंकर बनाए गए हैं और इन बंकरों के कारण सीमावर्ती इलाके में ज्यादा जनहानि नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सरकार सीमावर्ती इलाकों में और बंकर बनाएगी।

पुंछ में गोलाबारी से प्रभावित परिवारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, हम समझते हैं कि राहत और नौकरियां आपके द्वारा झेले गए दर्द और नुकसान की भरपाई नहीं कर सकती हैं। आपने अपने प्रियजनों को खो दिया है। जम्मू-कश्मीर सरकार, भारत सरकार और राष्ट्र की भावनाएं इस सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों से जुड़ी हुई हैं। सरकार जल्द ही गोलाबारी से प्रभावित परिवारों के लिए एक अलग पैकेज की घोषणा करेगी।

उन्होंने कहा, हम पहलगाम आतंकवादी हमले और जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा नागरिक क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों, स्कूलों पर हमले की निंदा करते हैं, जिसमें पुंछ जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। पुंछ जिले में पाकिस्तानी गोलाबारी में जुड़वां बहनों समेत कम से कम 14 नागरिक मारे गए हैं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि पहलगाम आतंकवादी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बावजूद जम्मू-कश्मीर में विकास कार्य नहीं रुकेंगे। मैं पुंछ के लोगों और उसके प्रशासन के साहस की प्रशंसा करता हूं; जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तानी गोलाबारी का जवाब दिया।

उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारतीय सशस्त्र बलों ने बहुत ही रणनीतिक और सटीक तरीके से मुंहतोड़ जवाब दिया और सात मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के बुनियादी ढ ांचे को नष्ट कर दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैकड़ों आतंकवादी मारे गए। हमारे बलों ने आतंकवादियों पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तान ने इसे खुद पर हमला माना और दुनिया को दिखाया कि वे आतंकवादियों को पनाह दे रहे हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान गोलाबारी से प्रभावित परिवारों को नियुक्ति पत्र भी सौंपे।

समरावता उपद्रव ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

परिस्थितितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में पुन: उन्हीं तथ्यों के आधार पर जमानत देना उचित नहीं है।

जमानत याचिका में कहा गया कि मामले की एफआईआर में नामजद आरोपियों में से 23 लोगों को पुलिस ने क्लीन चिट दी है। जबकि अदालत के समक्ष पूर्व में उनकी मामले में लिप्तता बताई गई थी और अदालत ने उन सभी को जमानत का लाभ दिया था। मामले में एसटी आयोग की जांच में भी पुलिस पर आरोप लगे हैं। ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

जमानत का विरोध करते हुए राज्य सरकार की ओर से जीए राजेश चौधरी ने कहा कि अदालत ने आरोपी की गत 14 फरवरी को जमानत याचिका खारिज की थी। उसके बाद आरोप पत्र पेश होने के बाद आरोपी पर चार्ज नहीं लगे हैं। ऐसे में जमानत याचिका को खारिज किया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

''सिंदूर''...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में निवेश और विकास का पूर्णतया अभाव है, जिससे नई नौकरियों का सृजन नहीं हो रहा है। मुर्शिदाबाद और माल्दा के दंगों का उल्लेख करते हुए ममता बनर्जी ने भाजपा पर इन घटनाओं की साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा का मकसद तृणमूल सरकार को अस्थिर करना है। उन्होंने पलटवार करते हुए, केन्द्र सरकार से सवाल किया कि मिज़ोरम में शांति बनाए रखने के लिए वह क्या कर रही है। हकीकत यह है कि जब तक ममता बनर्जी सत्ता में हैं और राज्य पुलिस एवं प्रशासन पर उनका नियंत्रण है, तब तक चुनावों में विपक्ष के लिए जीतना बेहद कठिन रहेगा। आरोप लगते रहे हैं कि चुनावी प्रक्रिया में केवल तृणमूल समर्थकों को ही प्रभावी रूप से मतदान करने की अनुमति दी जाती है, जिससे तृणमूल कांग्रेस की चुनावी जीत सुनिश्चित की जा सके।

'वर्ष 2026 के अंत ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मौजूद रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम संपन्न होने के बावजूद राम दरबार को दर्शनार्थियों के लिये खोला नहीं जायेगा क्योंकि इससे निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है मगर सभी मूर्तियों की विधिवत पूजा अर्चना शुरु हो जायेगी। उन्होने कहा कि देवोत्थान एकादशी के बाद भगवान विष्णु के शेषावतार की प्राण प्रतिष्ठा का एक और कार्यक्रम हो सकता है। मंदिर निर्माण अगले साल के अंत तक पूरा होने की संभावना है जो विशाल परिसर के साथ अपने भव्य रुप में होगा।

बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित तीन को उम्रकैद

कोटद्वार, 30 मई। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता हत्याकांड में आखिरकार अदालत ने शुक्रवार को सजा का एलान करते हुए मुख्य आरोपी पुलकित आर्य समेत तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनायी।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी की अदालत ने आज सजा का एलान किया। भाजपा के पूर्व नेता विनोद आर्या के पुत्र एवं ऋषिकेश के वनंतरा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 201 और 354 के तहत दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि रिसॉर्ट के प्रबंधक सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को साक्ष्य मिटाने के मामले में भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 302 और 201 के तहत दोषी ठहराते हुए दोनों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अवनीश नेगी के अनुसार तीनों को हत्या का दोषी करार दिया गया है और उम्रकैद की सजा सुनाई गयी है।

उल्लेखनीय कि वर्ष 2022 में अंकिता हत्याकांड सामने आया था। अंकिता ऋषिकेश के पास वनंतरा रिसॉर्ट में रिसेप्सनिष्ट के पद पर तैनात थी। वह 18 सितम्बर, 2022 को यकायक लापता हो गयी थी।

सेना प्रमुख द्विवेदी ने कश्मीर में सेना चौकियों का दौरा किया

जम्मू, 30 मई। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आज यहां जम्मू-कश्मीर के सुंदरबनी सेक्टर में अग्रिम इलाकों और चौकियों का दौरा कर क्षेत्र में स्थित विभिन्न सैन्य इकाईयों की परिचालन तत्परता का आकलन किया। जम्मू स्थित रक्षा प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने यहां कहा कि इस दौरान सेना प्रमुख को मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य और नियंत्रण रेखा पर सेना की परिचालन गतिशीलता के बारे में जानकारी दी गई जिससे मौजूदा रणनीतिक माहौल की व्यापक तस्वीर सामने आई। इस बीच सेना प्रमुख ने सैनिकों के साथ बातचीत में ऑपरेशन सिंदूर में उनके अनुकरणीय प्रदर्शन की सराहना की और सभी रैंकों को उनकी व्यावसायिकता, समर्पण और दृढ़ ता के लिए शाबाशी दी।

15 नर्सों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार

नयी दिल्ली, 30 मई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में विभिन्न वर्ग की 15 नर्सों को उनकी उल्लेखनीय सेवाओं के लिए वर्ष 2025 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया।

पुरस्कृत नर्सों में एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) वर्ग में अंडमान निकोबार की रेबा रानी सरकार, आंध्र प्रदेश की वलिवेती सुभावती, दादर-नगर हवेली एवं दमन-दीव की सरोज फकीरभाई पटेल, लक्षद्वीप की रजिया बेगम पीबी और महाराष्ट्र की सुजाता अशोक बागुल , एलएचवी (लेडी हेल्थ विजिटर) वर्ग में असम की बीना पानी डेका, नर्स वर्ग में अरुणाचल प्रदेश की किजुम सोरा कारगा, दिल्ली की डिम्पल अरोड़ा और मेजर जनरल शीना पी डी, कर्नाटक की डॉ बानू एमआर, मणिपुर की लीमापोकपम रंजीता देवी, मिजोरम की वी लालमंगई, पुडुचेरी की एलएस मणिमोझ़ी, तमिलनाडु की के अलामेलु मंगयारकरसी और पश्चिम बंगाल की डॉली बिस्वास शामिल हैं।

राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। इसका उद्येश्य उत्कृष्ट नर्सिंग कर्मियों को उनकी सराहनीय सेवाओं के लिए सम्मान देना है।

कांग्रेस ने शशि थरूर के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

- पर, शशि थरूर की ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में की गई, अमेरिका की यात्रा का कांग्रेस कोई लाभ नहीं उठा पायी।

द्वारा प्रतिनिधिमंडल के लिए चुने गए नाम पर आपत्ति जताई और कहा कि युसूफ पठान प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे, तो सरकार ने उनकी बात मान ली। इससे ममता को अपने नंबर दो नेता, अभिषेक बनर्जी को नामित करने का मौका मिल गया। इसके विपरीत, कांग्रेस ने थरूर को टीम में शामिल होने की स्वीकृति नहीं दी, बल्कि उसने कहा कि यह पूरी कवायद प्रधानमंत्री मोदी को उन कठिन सवालों से दूर रखने के लिए की जा रही है, जिनका उत्तर प्रधानमंत्री से मांगा जा रहा है।

एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने स्वीकार किया कि अगर सरकार ने शुरुआत में ही अभिषेक बनर्जी का नाम प्रस्तावित किया होता, तो ममता कोई विवाद खड़ा ही नहीं करतीं। अभिषेक बनर्जी सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए इस बात पर जोर दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस भी राष्ट्रवाद पर उतनी ही आक्रामक हो सकती है जितनी कि भाजपा। टोक्यो में उन्होंने कहा, ''अगर आतंकवाद एक पागल कुत्ता है, तो पाकिस्तान उसका गंदा रखवाला है। हमें पहले इस जंगली रखवाले को काबू में करना होगा - नहीं तो यह और भी पागल कुत्ते पैदा करता रहेगा।'' अभिषेक के इस बयान का तृणमूल कांग्रेस खूब प्रचार कर रही है। टोक्यो में अभिषेक ने रास बिहारी बोस के स्मृति-स्थल का दौरा किया और उसकी उपेक्षित और जीर्ण-शीर्ण हालत के मुद्दे को उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मैंने हमारे राजदूत और टोक्यो स्थित भारतीय दूतावास से अनुरोध किया है कि वे संबंधित अधिकारियों के साथ इस मुद्दे को उठाएं और सुनिश्चित करें कि इस अद्वितीय वीर को वह सम्मान मिले जिसके वे वास्तव में हकदार हैं।

मोदी अपने मंत्रिमण्डल में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कर दिया है। कांग्रेस नेतृत्व इस अभियान से बार-बार दूरी बनाता रहा है, यह कहते हुए कि इससे मतदाता ध्रुवीकृत हो सकते हैं। थरूर का स्वतंत्र रुख उनके सत्ताधारी दल के प्रति बढ़ते झुकाव की अटकलों को और तेज कर रहा है।

कांग्रेस की मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब वरिष्ठ पार्टी नेता और कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य सलमान खुर्शीद ने अपनी इंडोनेशिया यात्रा के दौरान सुर्खियां बटोरीं। प्रमुख बुद्धिजीवियों से बातचीत के दौरान एक चौंकाने वाले बयान में खुर्शीद ने अनुच्छेद 370 के हटाए जाने का समर्थन किया। जबकि यहएक ऐसा मुद्दा है, जिसका कांग्रेस परंपरागत रूप से विरोध करती रही है। उन्होंने जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनावों में 65 प्रतिशत मतदान को लोकतांत्रिक जुझारूपन का प्रमाण बताया। उनके बयान ने कांग्रेस खेमे में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि कई नेता इसे पार्टी लाइन से अलग रुख मान रहे हैं। इस बीच, पंजाब से कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने एक और तूफान खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के वैश्विक नैरेटिव का जवाब देने के लिए एक प्रमुख कूटनीतिक मिशन के लिए अपने ही दल द्वारा नज़रअंदाज़ किए जाने के बाद, तिवारी से कथित रूप से सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय ने संपर्क किया। पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी के साथ तनावपूर्ण संबंधों के लिए चर्चा में रहे तिवारी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जिससे कांग्रेस के भीतर अंदरूनी तनाव और बढ़ गया है। सूत्रों का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अपने मंत्रिपरिषद में बड़ा फेरबदल करने की योजना बना रहे हैं, जिसमें प्रदर्शन में पिछड़ रहे कई भाजपा नेताओं को हटाया जा सकता है। इस कदम का उद्देश्य महत्वपूर्ण राज्य चुनावों से पहले शासन व्यवस्था को नई ऊर्जा देना और मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री की बदलती राजनीतिक और कूटनीतिक सोच के अनुरूप बनाना है। जैसे-जैसे गठबंधन बदल रहे हैं और वफादारियों की सीमाएं धुंधली हो रही हैं, आने वाले हफ्तों में भारतीय राजनीति का सत्ता संतुलन पूरी तरह से बदल सकता है-इसके दूरगामी असर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों पर पड सकते हैं।

सलेक्टिव मीडिया, कोटा के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी रोड, कोटा से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा आर.एन.आई. नं. 28446/75, जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908